भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 147*

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्य–निष्पादन

147*. डा॰ टी॰ एन॰ सीमाः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लक्षित विभिन्न योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/ आजीविका और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास उपलब्ध निगरानी–तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री जयराम रमेश)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर में सुधार ग्रामीण विकास योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन सहित विभिन्न कारकों निर्भर करता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) लोगों की संख्या में कमी वह संसूचक है, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार का पता चलता है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (बीपीएल) लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच 32.63 करोड़ से कम होकर 21.65 करोड़ रह गई है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2010-11, 2011-12 और 2012-13) तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष 2013-14 (नवम्बर, 2013 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की वित्तीय और वास्तविक प्रगति का ब्यौरा अनुबंध में दर्शाया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी के लिए आवधिक प्रगति रिपोर्टों / प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, राज्य / जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों तथा राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं के माध्यम से एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को 5 सूत्री कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है, जिसके 5 सूत्र इस प्रकार हैं (i) योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना (ii) पारदर्शिता (iii) लोगों की भागीदारी (iv) जवाबदेही, सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार के लिए सभी स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 16.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में नवम्बर, 2013 तक मनरेगा, एसजीएसवाई/एनआरएलएम और एनएसएपी की अखिल भारतीय वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

(रू. करोड़ में)

वित्तीय उपलब्धि

कार्यक्रम का नाम	2010-11			2011-12			2013-13			2013-14		
	उपलब्ध निधियां	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध निधियां	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध निधियां	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध निधियां	उपयोग	उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मनरेगा	54172.14	39377.27	73.00	48805.68	37072.82	76.00	45051.43	39657.04	88.00	35586.10	20859.96	59.00
एसजीएसवाई/ एनआरएलएम	3744.10	2800.61	74.80	2977.33	2318.14	77.86	3284.16	1012.33	30.82	NR	328.31	0.00
एनएसएपी	6756.93	5276.66	78.09	8024.33	6153.63	76.69	9685.93	6910.69	71.35	8650.05	3215.02	37.17

वास्तविक उपलब्धि

कार्यक्रम का नाम	2010-11		2011-12		2013-13		2013-14		इकाई
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मनरेगा*		25715		21876		22986		11074	लाख श्रम दिवसों में सृजित रोजगार
एसजीएसवाई/ एनआरएलएम	21.77	21.09	19.81	16.77	18.87	11.44	NR	NR	सहायता प्राप्त स्व-रोजगारियों की कुल संख्या (लाख में)
एनएसएपी *		169.62		207.45		223.21		7.42	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या लाख में

*मनरेगा और एनएसएपी के तहत लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं।

2011-12 से एसजीएसवाई को पुनर्गठित करके एनआरएलएम नाम दे दिया गया है।